



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड : 49	शिमला, शनिवार, 17 मार्च, 2001/26 फाल्गुन, 1922	संख्या : 11
	विषय सूची	
भाग-1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	2818—2819
भाग-2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	—
भाग-3	अधिनियम; विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फार्मैलैशियल कमिशनर तथा कमिशनर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	2819—2828 तथा 2842—2850
भाग-4	स्थानीय स्वायत्त शासन, म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाऊन एरिया तथा पंचायती राज विभाग	2828—2832
भाग-5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	2832—2842 तथा 2850
भाग-6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में पुनः प्रकाशन	—
भाग-7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

17 मार्च, 2001/26 फाल्गुन, 1922 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निर्मातव्य विज्ञप्तियों 'समाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं:—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
No. SEC, 16-18/96-v-313-14, dated 13th March, 2001.	State Election Commission, Himachal Pradesh	Special revision of electoral rolls for the conduct of election in Lahaul & Spiti and Pangti Sub-Division of Chamba district.
No. Fin-2-C (2)-1/2000, dated 16th March, 2001.	Finance Department	Issue of 10.50 per cent Himachal Pradesh State Development Loan, 2011 of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs. 50.00 crore (nominal).

भाग-1 - वैधानिक नियमों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

Solan, but for his proceeding on leave for the above period.

NOTIFICATIONS

Shimla-171 002, the 27th February, 2001

By order,

Sd/-
Registrar (Vigilance).

No. HHC/GAZ/14-190/88-3331.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant *ex post facto* sanction of 25 days earned leave with effect from 7-1-2001 to 31-1-2001 in favour of Shri K. P. Singh, Additional Chief Judicial Magistrate-cum-SJIC, Jawali.

Certified that Shri K. P. Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri K. P. Singh would have continued to hold the post of Additional Chief Judicial Magistrate-cum-SJIC, Jawali, but for his proceeding on leave for the above period.

This is in continuation of this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-190/88-24352-61, dated 1-12-2000.

Shimla-2, the 1st/2nd March, 2001

No. HHC/GAZ/14-196 89-I-3535.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant *ex post facto* sanction of 2 days commuted leave *i. e.* for 12th and 13th February, 2001 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 10th and 11th February, 2001 in favour of Shri K. K. Sharma, Additional Chief Judicial Magistrate-cum-SJIC (I), Amb.

Certified that Shri Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the Post of Additional Chief Judicial Magistrate-cum-SJIC (I), Amb, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-2, the 1st/2nd March, 2001

No. HPHC/GAZ/14-138/82-I-3527.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 13 days earned leave *w.e.f.* 12-3-2001 to 24-3-2001 with permission to prefix gazetted holidays falling on 9th, 10th and 11th March, 2001 and to suffix Sunday falling on 25th March, 2001 in favour of Shri R. L. Azad, Senior Sub Judge-cum-CJM, Kangra at Dharamshala.

Certified that Shri Azad is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Azad would have continued to hold the post of Senior Sub-Judge-cum-CJM, Kangra at Dharamshala, but for his proceeding on leave for the above period.

Shimla-171001, the 1st/2nd March, 2001

No. HHC/GAZ/14-131/82-II-3516.—Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 32 days earned leave *w.e.f.* 12-3-2001 to 12-4-2001 with permission to prefix gazetted holidays falling on 9th, 10th and 11th March, 2001 and to suffix gazetted holidays falling on 13th, 14th and 15th April, 2001 in favour of Shri K. L. Sharma, Senior Sub-Judge-cum-CJM, Solan.

Certified that Shri Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of Sub-Judge-cum-CJM,

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL (A-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th February, 2001

No. Per (A-I) B (3) 53/87-Vol. VI.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri N. S. Chaudhary, HAS, Additional Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh shall also hold the additional charge of the post of Additional Secretary (Technical Education, Printing & Stationery) to the Government of Himachal Pradesh during the leave period of Shri Virendra Kumar, IAS (HP : 87).

By order,

Sd/-
Chief Secretary.

AYURVEDA DEPARTMENT

ADDENDUM

Shimla-171002, the 6th February, 2001

No. Ayur-Ga (1)-3/97.—Please add words "Ayurvedic Medical Officer" before the words "Pharmacist" appearing in line 3 of para 3 of this Department's Notification of even number, dated 30-1-2001.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary (Ayurveda).

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 3rd February, 2001

No. JHP-A-23(8)-1/2000.—In this department notification of even number, dated 2nd February, 2001, posting of following executive Engineer (C) IPH may be read as under:—

Name of EE	Place of posting
Shri Nawal Kishore Gupta	EE(D) P&I-II, Shimla against vacancy.
Shri Sanjeev Kaul	EE(D) P&I-I, Shimla against vacancy.

By order,

Sd/-
F.C.-cum-Secretary.

बहुदेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 फरवरी, 2001

संख्या विद्युत-छ(5) 6/2000.—प्रति: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश का यह प्रतीक होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास

अधिकरण (हिमऊर्जा) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अन्तर्गत एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव फाटी पलचान, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) में लघु पन बिजली परि- योजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव: एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 मार्च, 2001

संख्या पी0एल जी0एफ0सी0(एफ) 1-9/94-131-खण्ड-III.— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कोटला खुर्द, तहसील एवं जिला ऊना में नगल-तलवाड़ा रेल लाईन (ऊना से चुरहू तक) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और अधिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमन अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कयित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तोंस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला ऊना (नहायक उपायुक्त, ऊना) हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला : ऊना	तहसील : ऊना
गांव	खसरा नं०
कोटला खुर्द	1567/1
	2867
	2868/1
	2843
किता .. 4	0 20 68

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

By order,

HARSH GUPTA,
Addl. C.S.-Cum-Secretary.

भाग-2—वैधानिक नियमों को छोड़कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

-शून्य-

भाग-3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनैशियल कमिशनर तथा कमिशनर ऑफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

LABOUR DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-1, the 14th February, 2001

No. 11-1/85 (Lab) I. D.—In partial modification of this Department Notification of even number, dated

19-1-2001, the name mentioned at the title of the reference as Rajinder Kumar be substituted by: Rajesh Kumar and the name of Shri Sawaran Chand Katoch, be deleted.

Sd/-
Labour Commissioner.

अधिसूचनाएं

शिमला-171001, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-1/86 (लैब) आई० डी०-भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rakesh Kumar, Ex-daily wages beldar and the General Manager, Rosin and Turpentine Factory, Nahan, District Sirmaur (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

1. "Whether the termination of services of Sh. Rakesh Kumar, Ex-daily wages beldar w. e. f. 3/97 by the General Manager, Rosin and Turpentine Factory, Nahan, District Sirmaur (H. P.) without any notice, chargesheet, enquiry and without compliance of section 25(F) of the Industrial Disputes Act, 1947 on completion of 240 days continuous service, as alleged, is legal and justified. If not, to what relief of service benefits and amount of compensation, Shri Rakesh Kumar is entitled?"
2. "Whether Shri Rakesh Kumar has left the service on his own, as alleged. If so, its effect?"

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-23/84 (लैब) आई० डी०-भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Dina Nath Ex-daily wages beldar and Executive Engineer, Irrigation and Public Health, Division Mandi, District Mandi, (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of Shri Dina Nath, Ex-daily Wages beldar, by the Executive Engineer, Irrigation and Public Health Division, Mandi, District Mandi (H. P.) without any

notice, chargesheet, enquiry and without compliance of section 25(F) of the Industrial Disputes Act, 1947 as alleged is legal and justified. If not, to what relief of service benefits and amount of compensation, Shri Dina Nath is entitled?"

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-23/84 (लैब) आई० डी०-भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि S/Shri Prem Singh, Tara Chand, Dharam Chand and Jayoti Singh, Ex-worker and (1) Managing Director M/s Karam Chand Thapar & Bros. Ltd., Hydro Consult Division (UHL-III HEP), 124 Janpath, New Delhi-110001 and (2) Assistant Engineer M/s Karam Chand Thapar & Bros. Ltd. Hydro Consult Division (UHL-III HEP), Bawa Building Main Bazar Jogindernagar, District Mandi, (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम देने के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

"Whether the termination of services of S/Shri Prem Singh, Tara Chad, Dharam Chand and Jayoti Singh, Ex-worker w. e. f. 30-9-99, by (1) Managing Director M/s Karam Chand Thapar and Bros. Ltd., Hydro Consult Division (UHL-III HEP), 124 Janpath, New Delhi-110001 and (2) Assistant Manager M/s Karam Chand Thapar and Bros. Ltd., Hydro Consult Division (UHL-III HEP), Bawa Building, Main Bazar, Jogindernagar, District Mandi, H. P. without any notice, chargesheet, enquiry in violation of section 25(F) and 25 (N), of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged, is legal and justified. If not to what relief of consequential service benefits and amount of compensation, the above aggrieved workmen are entitled?"

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-2/86 (लैब) आई० डी०-भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Amar Singh, Ex-gardner and the Divisional Forest Officer, Bilaspur, District Bilaspur (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के

अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिये भेजा जाता है :—

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the termination of services of Shri Amar Singh, Ex-gardner w. e. f. 1-7-97 by the Divisional Forest Officer, Bilaspur, District Bilaspur, without any notice, chargesheet, enquiry and without compliance of section 25(F) of the Industrial Disputes Act, 1947 on completion of 240 days continuous service, as alleged, is legal and justified. If not, to what relief of consequential service benefits and amount of compensation, Shri Amar Singh is entitled?”

शिमला-171001, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-2/86 (लैब 0) आई 0 डी 0 भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Roop Lal, Ex-daily Wages Beldar and the Divisional, Forest Officer, Forest Division, Bilaspur (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है।

“Whether the termination of services of Shri Roop Lal, Ex-daily wages beldar by the Divisional Forest Officer, Forest Division, Bilaspur, District Bilaspur, H. P. w. e. f. 1-1-91 without, any notice, chargesheet, enquiry and in violation of section 25(B), 25(F) and 25(H) of the Industrial Disputes Act, 1947 by retaining Junior persons in service, as alleged, is legal and justified. If not, to what relief of service benefits and amount of compensation, Shri Roop Lal is entitled?”

शिमला 1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-23/84 (लैब) आई 0 डी 0 भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Duggal Ram, Ex-daily wages beldar and (1) Secretary, H. P. State Electricity Council, Shimla and, (2) Executive Engineer, H. P. State Electricity Council, Division Manali, District Kullu, H. P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन

1. “Whether the termination of service of Shri Duggal Ram, Ex-daily wages beldar w. e. f. 21-4-89 by (1) Secretary, H. P. State Electricity Council, Shimla and (2) Executive Engineer, H. P. State Electricity Council, Division, Manali, District Kullu, (H. P.) without any notice, chargesheet, enquiry and without compliance of section 25 (F) of Industrial Disputes Act, 1947, on completion of more than 240 days continuous service, as alleged, is legal and justified. If not, to what relief of consequential service benefits and amount of compensation, Shri Duggal Ram is entitled?”

2. “Whether Shri Duggal Ram has left the service on his own, as alleged. If so its effect?”

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-23/84 (लैब 0) आई 0 डी 0 भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Secretary, All Unskilled Workers of H. P. M. C. Jarol, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. and (1) Managing Director H. P. M. C. Shimla, (2) Manager, H. P. M. C. Jarol, and (3) M/s B. D. M. Company, Jarol, Tehsil Sundernagar, District Mandi, (H. P.) के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the demands raised by the Secretary All Unskilled Workers of H. P. M. C. Factory, Jarol, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. with (1) Managing Director, H. P. M. C. Shimla, (2) Manager, H. P. M. C. Jarol and, (3) M/s B. D. M. Company, Jarol, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P. for their regularisation on completion of 10 years service as prescribed by taking into consideration their lease period with the B. D. M. Company and further their demand for wages as per their skill, is reasonable and justified. If yes, to what relief of service benefits including regularisation, wages and amount of compensation, the above un-skilled workers are entitled?”

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-1/96 (लैब) आई 0 डी 0 भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Nisar Ali, Ex-beldar and (1) Executive Officer, Municipal Committee, Paonta Sahib, District Sirmaur and, (2) the Director, Urban Development, Shimla-2 (H. P.) के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई

रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम(लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1997 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Nissar Ali by (1) Executive Officer, Municipal Committee, Poanta Sahib, District Sirmaur, H. P. and (2) The Director, Urban Development, Himachal Pradesh, Shimla-2 w. e. f. 3-10-88 without any notice, chargesheet, enquiry and without compliance of section 25 (F) of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged is legal and justified. If not, to what relief of service benefits and amount of compensation, Shri Nissar Ali is entitled?"

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-6/85 (नैब0) आई0 डी0-भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Hans Raj, Ex-daily wages beldar and the Executive Engineer, I. & P. H. Division Arki, District Solan (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

1. "Whether the termination of services of Shri Hans Raj, Ex-daily wages beldar by the Executive Engineer, I. & P. H. Division Arki, Tehsil Arki, District Solan, H. P. w. e. f. 31-8-98 without any notice, chargesheet, enquiry on completion of 240 days' continuous service in violation of section 25 (F) and 25 (N) of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged is legal and justified. If not, to what relief of consequential service benefits and amount of compensation, Shri Hans Raj is entitled?"

2. "Whether Shri Hans Raj has left the job on his own, as alleged. If so, its effect?"

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-1/86 (नैब0) आई0 डी0-भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Bal Krishan, Ex-daily Wages Beldar and Divisional Forest Officer, Forest Division Taruwala, Tehsil Poanta Sahib, District Sirmaur (H.P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम(लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Bal Krishan, Ex-daily wages beldar by the Divisional Forest Officer, Forest Division Taruwala, Tehsil Poanta Sahib, District Sirmaur, H. P. in the year 1991 without compliance of section 25(F) of the Industrial Disputes Act, 1947, on completion of 240 days' continuous service, as alleged, is legal and justified. If not, to what relief of service benefits and amount of compensation, Shri Bal Krishan is entitled?"

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-1/85 (नैब0) आई0 डी0-भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sawaran Chand Katoch and management of M/s Palampur Co-operative Tea Factory Ltd. P. O. Maranda, District Kangra (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Sawaran Chand Katoch by the Chairman, Palampur Co-operative Tea Factory Ltd., P. O. Maranda District Kangra, H. P. without any notice, chargesheet, enquiry and without compliance of section 25 (F) of the Industrial Disputes Act, 1947, is legal and justified. If not, to what relief of amount of compensation, the above aggrieved workman is entitled?"

शिमला-171 001, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-1/85 (नैब0) आई0 डी0-भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Pushpa Rani, worker and (1) The Manager, Nurpur Silk Mills Nurpur, District Kangra and (2) The Managing Director, H. P. General Industries Corporation Ltd., Himrus Building Shimla-1 (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त

अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the demand raised by Smt. Pushpa Rani, worker through the General Secretary, Small Scale Industries Workers Union (Regd.) Nurpur Bodh, District Kangra, H. P. and (2) the Managing Director, H. P. General Industries Corporation Ltd., Himrus Building, Shimla-1 for change in her date of birth from 11-4-42 to 11-4-57 at his belated stage in spite of her appointment in the year 1982 and in violation of Certified Standing Orders, is legal and justified. If yes, to what relief Smt. Pushpa Rani is entitled?”

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-1/86 (लैब) आई० डी० भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Sikandar, Ex-worker and Managing Director M/s Umesh Industrial Enterprises Pvt. Ltd., Kala Amb, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89 श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the demand of Shri Sikandar, Ex-worker from the Managing Director M/s Umesh Industrial Enterprises Pvt. Ltd., Kala Amb, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H. P. for his reinstatement after receiving full and final payment of all his legal claims/dues, as alleged, is legal and justified. If not, to what effect?”

शिमला-1, 14 फरवरी, 2001

संख्या 11-1/86 (लैब) आई० डी० भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Mahanti Devi and Smt. Jaitoon Begum and (1) Chief Engineer, H. P. P. W. D./I. & P. H. State Workshop (Nahan Foundry) Nahan and (2) The Superintending Engineer, H. P. P. W. D./I. & P. H. State Workshop (Nahan Foundry) Nahan and (3) The Executive Engineer, H. P. P. W. D./I. P. H. State Workshop (Nahan Foundry) Nahan, District Sirmaur (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8-89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किये गये विषय पर अधिनियम देने के लिए भेजा जाता है :—

“Whether the retirement of Late Sarv/Shri Kesho Ram and Bundu Khan, Ex-workers by (1) The Chief Engineer, H.P.P.W.D./I. & P. H. State Workshop (Nahan Foundry), Nahan and (2) The Superintending Engineer, H.P.P.W.D./I. & P. H. State Workshop (Nahan Foundry) Nahan, and (3) The Executive Engineer, H.P.P.W.D./I. & P. H. State Workshop (Nahan Foundry) Nahan, District Sirmaur, H. P. at the age of 58 years instead of 60 years in violation of Fundamental Rule 56 (B) as alleged, and whether the demand of Smt. Mahanti Devi and Smt. Jaitoon Begum dependents (Wives) of the deceased for consequential service benefits admissible to the above deceased workers between the date of actual retirement (58 years) and date of retirement (60 years) as claimed, is legal and justified. If yes, to what relief of consequential service benefits and amount of compensation the above dependents are entitled?”

शिमला-1, 17 फरवरी, 2001

संख्या 11-2/93 (लैब) आई० डी० भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Parkash Chand, Ex-turner and the Management of M/s Raja Forgings & Gears Ltd., (Gear Division), Sai Road Baddi, District Solan (H. P.) के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि यह मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनियम के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम-न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गये विषय पर अधिनियम के लिए भेजा जाता है :—

1. “Whether the termination of services of Shri Parkash Chand, Ex-turner (Token No. 3098) by the management of M/s Raja Forgings and Gears Ltd., (Gear Division), Sai Road Baddi, District Solan, H. P. w. e. f. 13-3-99 in the garb of transfer to Panchkula Unit, as alleged, is legal and justified. If not, to what relief of service benefits and amount of compensation, Shri Parkash Chand is entitled?”

2. “Whether the enquiry conducted by the employer can be termed as fair and proper in

view of the fact that Shri A. K. Sharma was the enquiry officer and simultaneously the representative of the employer before the Conciliation Officer during the conciliation proceedings, as alleged. If not, its effect?"

शिमला-1, 1 मार्च, 2001

संख्या 11-6/85 (सैब) आई0 डी0 भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Sonia, Ex-helper and the Executive Engineer, H. P. Housing Board (Electrical Division) Shimla-2 के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिये भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिये भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Smt. Sonia, Ex-daily wages helper by the Executive Engineer H. P. Housing Board (Electrical Division) Shimla-2 w. e. f. 14-8-2000 without compliance of section 25 (F) of the Industrial disputes Act, 1947, on completion of 240 days continuous service, as alleged, is legal and justified. If not, to what relief of service benefits and amount of compensation, Smt. Sonia is entitled?"

शिमला-171 001, 1 मार्च, 2001

संख्या 11-6/85 (सैब0) आई0 डी0 भाग.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि General Secretary/Pradhan, Employees Union Central Co-operative Consumer Store, Shimla and (1) The Managing Director, H. P. State Marketing and Consumers Co-operative Federation Ltd., Shimla-3 and (2) Liquidator, Co-operative Consumers Store c/o Registrar, Co-operative Societies, Himachal Pradesh, Shimla-9 (H. P.) के मध्य नीचे दिये गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the demands raised by the Pradhan/General Secretary, Employees Union, Central

Co-operative Consumer Store, Shimla with (1) The Managing Director, H. P. State Marketing and Consumers Co-operative Federation Ltd., Shimla-3 (2) liquidator, Co-operative Consumer Store c/o Registrar, Co-operative Societies, Himachal Pradesh, Shimla-9 vide their demand notice dated 30-1-2000 for grant of pay scales, annual increment, additional dearness allowance, interim relief and other regular allowance admissible to them w. e. f. 18-6-94 as a result any alleged settlement arrived at in between employer No. 1 and the union besides revised pay scales w. e. f. 1996, are genuine and justified? If yes, which of their demand should be accepted and from which date?"

शिमला-1, 1 मार्च, 2001

संख्या 11-23/84-(सैब0) आई0 डी0 भाग-IV.—अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Prem Chand Sharma and (1) Secretary, H. P. State Electricity Board Shimla-4 and (2) Executive Engineer, Electricity Board, Division Bilaspur, District Bilaspur, (H. P.) के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) के अधीन विचार करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19-8/89-श्रम (लूज), दिनांक 7 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है:—

"Whether the termination of services of Shri Prem Chand Sharma, Ex-worker by (1) Secretary, H. P. State Electricity Board, Shimla-4 and (2) Executive Engineer, Electricity Board, Division Bilaspur, District Bilaspur, H. P. without any notice, charge-sheet, enquiry in violation of section 25 (F), 25 (G) and 25 (H) of the Industrial Disputes Act, 1947 by ignoring the Principal of "First Come, last go", as alleged, is legal and justified. If not, to what relief of consequential service benefits, Shri Prem Chand is entitled?"

हस्ताक्षरित/-
श्रमायुक्त।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 फरवरी, 2001

संख्या मुद्रण (बी) 2-21/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मैकेनिक (विद्युत) वर्ग-III (अराजपति) अतिरिक्त वर्गीय सेवाएं पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मैकेनिक (विद्युत) वर्ग-III

(अराजक) अतिरिक्त वर्गीय सेवाएं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां—इन विभाग की अधिमूर्चना संख्या Y 4-26/75-अरोमु(स्था.)-II-तारीख, 20-9-1979 द्वारा अधिमूर्चित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग वर्ग-III (निपिक वर्गीय तथा तकनीकी सेवा) (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 1979 का उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, जहां तक कि ये मैकेनिक (विद्युत) के पद को लागू हों।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विद्यमान रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव।

उपाध्यक्ष-"क"

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश में मैकेनिक (विद्युत) वर्ग-III के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम मैकेनिक (विद्युत)
2. पदों की संख्या 2 (दो)
3. वर्गीकरण वर्ग-III (अराजक) अतिरिक्त वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान रुपये 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160.
5. न्यूनतम पद अथवा अधिकतम पद लागू नहीं
6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु 18 से 40 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए उच्चतम आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के माधुरण या विशेष आदेशों के अधीन अनन्य है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों

के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में शामिल हो चुके हों, मर्यादी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही गिरावट दी जाएगी जैसी मर्यादी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पञ्चायतों/ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गये हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से शामिल किए गये हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.— (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें आवेदन प्रार्थना करने के लिए, यथास्थिति, पद विज्ञापित या नियोजनानुसार प्रेषित किए जाते हैं।

(2) अभ्यर्थी सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार निर्धारित किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।

- अनिवार्य अर्हताएं :
- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड में 10वीं/हायर सेकेंड्री भाग-I या इसके समकक्ष
 - (2) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में मैकेनिक (इलेक्ट्रिकल) ट्रेड में 3 वर्ष का प्रमाण-पत्र कोर्स या इसके समकक्ष।
 - (3) बिजली के उपकरणों/मीटरों/तारों को ठीक करने में उनका रख-रखाव और अनुरक्षण का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो।

वांछनीय अर्हताएं :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, नीतियों और वोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता

आयु : लागू नहीं

शैक्षणिक योग्यताएं : लागू नहीं

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं ?

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष में अधिकतम एक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पदतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या लागू नहीं
स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियों जिस : प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं
समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना ?
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।
किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।
सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम, यथास्थिति आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
16. आरक्षण
उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा
लागू नहीं
18. शिथिल करने की शक्ति
जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद की बाबत शिथिल कर सकेगी।

of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Mechanic (Electrical) Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial Services in the Department of Printing & Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing & Stationery Department, Mechanic (Electrical) (Class-III Non-Gazetted) Non-Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2001.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Class-III (Ministerial and Technical) Service (Recruitment and Promotion and certain condition of Services) Rules, 1979 notified vide this department notification No. 14-26/75-Shromu (Satha)-II, dated 20-9-79 are hereby repealed to the extent these are applicable to the post of Mechanic (Electrical).

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

Financial Commissioner-cum-Secretary.

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MECHANIC (ELECTRICAL) NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY HIMACHAL PRADESH

- | | |
|--|---|
| 1. Name of the post | Mechanic (Electrical) |
| 2. Number of posts | 2 (Two) |
| 3. Classification | Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services. |
| 4. Scale of pay | Rs. 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160. |
| 5. Whether selection post or non-selection post? | Not applicable |
| 6. Age for direct recruitment. | Between 18 and 40 years: |

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

[Authoritative English text of this Department Notification No. Mudran(B)2-21/99, dated 20-2-2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th February, 2001

No. Mudran (B)2-21/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

Essential Qualification :

(i) Matric/Higher Secondary Part-I or its equivalent from a recognised University/Board.

(ii) Three years Certificate Course in the trade of Mechanic (Electrical) or its equivalent from an I. T. I. or an Institution duly recognised by the Central/State Government.

(iii) Three years practical experience in the repair, maintenance and upkeep of electrical equipments, motors and wiring.

Desirable Qualification :

Knowledge of customs, manners and dialects of

Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

Age : Not applicable.
Educational Qualification : Not applicable

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.

9. Period of probation, if any.

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

100% by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.

Not applicable

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

Not applicable

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.

As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test in Himachal Pradesh Public Service Commission or other Recruiting Authority as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test, or practical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Commission/other Recruiting Authority as the case may be.

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.

Not applicable

18. Powers to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the

Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

भाग-4—स्थानीय स्वायत्त शासन, म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

ORDERS

Shimla-171009, the 13th December 20001

No. PCH-HA (5)68/99.—That Shrimati Sneh Lata, Pradhan Gram Panchayat Lambloo, Development Block Hamirpur, District Hamirpur was placed under suspension for the following allegations :—

1. That Shrimati Sneh Lata, Pradhan remains out of the Sabha Area except on days fixed for meetings of Gram Panchayat, which causes grave inconveniences to the public in getting their works done. The G. P. has passed a Resolution No. 2 dated 26-5-1999 to this effect. That the said Pradhan does not take other members into confidence and decides issues at her own whims. Neither the said Pradhan puts forth the Dak of the Panchayat nor does she maintain it in the records. The G. P. has quoted an instance of Shri Mulak Raj s/o Shri Durga Dass. This fact has also been corroborated by the statement made by the said Pradhan during preliminary inquiry wherein she insisted that she would work at her own way though complaint can be made against her for it. This fact proves that Shrimati Sneh Lata is misusing the powers, responsibilities of the post of Pradhan besides neglecting the provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.
2. That the Pradhan decides judicial cases at the instance of her husband and her husband interferes in the proceedings of the G.P. which was objected to by all the members of the G.P. Her husband also advises her for imposing fines etc. The fines imposed on accused are not entered into cash book which shows that the disputed cases are decided at her own level and the rest of the members are not apprised of the decision.
3. That the said Pradhan passed a resolution dated 11-7-1998 for withdrawing Rs. 27000/- at the instance of her husband and misused the same. This resolution has been entered at P-76 of the proceeding register.
4. That as per Resolution No. 6 dated 11-9-1998 and letter No. 7034-37 dated 29-10-1998, letter No. 6574 dated 28-9-1998 from BDO Hamirpur and subsequent Resolution No. 9 & 11 dated 26-3-1999, the said Pradhan refused to sign the cheques, meant for withdrawing funds for development works by neglecting above mentioned directions/ letters. This shows that the said Pradhan disposes off the cases of G.P. at her own whims. By this hindrance the construction work of the Community Centre, Dabrera could not be completed.
5. That Rs. 10000/- were sanctioned for the construction of link road leading from Talai to Broli Kalan. Against this amount the said Pradhan has kept receipt of Rs. 3850/- as expenditure incurred in the scheme in the name of Shri Jogi Ram, the Mule owner. The said Shri Jogi Ram stated in his statement that he has received Rs. 300/- only. In addition to it, two receipts of Rs. 2400/- and Rs. 1425/- have been booked in the cash-book, but the said Shri Jeet Ram has not received this payment and his signatures

have also been found forged. The name of the said person is Ajeet Singh and not Jeet Singh. This shows that Rs. 5000/- have not been spent on the scheme and the expenditure is doubtful.

6. That as per the preliminary inquiry Rs. 13301/- has been shown as expenditure by the said Pradhan and Panch Shrimati Urmila. Neither the labourers whose names have been shown in the muster-rolls, have not worked under the scheme nor they received any payment. Hence, the said Pradhan has embezzled following amounts by preparing fake bills/vouchers.

Sl. No.	Name of the labourer	Vocher No. & date	Description
1	2	3	4
1.	Shri Nek Ram (member of construction committee)	40/26-10-97 05/27-7-97 09/31-7-96 10/13-8-96 11/31-3-97	Muster roll of October, 97. 8 bags of cements Muster roll of July, 98. Muster roll of Aug., 96. Muster roll of March, 97.
2.	Shrimati Geeta Devi (member of construction committee)	15/11-8-97 16/11-8-97 19/15-9-97 20/15-9-97 21/15-9-97 38/26-10-97 39/26-10-97 40/26-10-97 05/27-7-96 10/13-9-96 11/31-3-97	14 bags of cement Muster roll of June, 97. 2 bags of cement, 22 trips of hourse charges. Muster roll of July, 97. 5 bags of cement 17 bags of cement Muster roll of October, 97. 8 bags of cement Muster roll of August, 96. Muster roll of March, 97.
3. (i)	Shri Praveen Kumar, Village Thankari	15/1-8-97	14 bags of cement
(ii)	Meera Devi w/o Shri Vidhi Chand, Village Thankari	19/15-9-97	2 bags of cement
(iii)	Shri Roshan Lal s/o Shri Chaudari Ram, Village Thankari	20/15-9-97 21/15-9-97 38/26-10-97 39/26-10-97 05/27-7-96 09/31-7-96 11/31-3-98	22 bags of cement Muster roll of July, 97 5 bags of cement 17 bags of cement 8 bags of cement Muster roll of July, 96. Muster roll of March, 97.
4.	Shri Hoshanki Rams/o Shri Laturia Ram, Village Thankari	19/15-9-97 16/15-9-97 21/15-9-97 38/26-10-97 05/27-7-96	2 bags of cement 22 trips of hourse for bolders. Muster roll of July, 97 5 bags of cement. 5 bags

1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Shri Swatanter Kumars/o Shri Hem Raj	15/11-8-97 16/11-8-97 19/15-9-97 20/15-9-97 21/15-9-97 10/13-8-96 11/31-3-97	14 bags of cement Muster roll of January. 97 2 bags of cement 22trips of hourse for bolders. Musterroll of July, 97. Muster roll of August 96. Muster roll of March 97.	2.	16 of 11-8-97	Jogi Ram s/o Shri Ghungar Ram	675
				3.	16 of 18-8-97	Pravin Kumar s/o Dina Nath	405
						Total ..	1,755

In addition to this, Enquiry Officer has also pointed out that some of the signatures of members of Development Committee on the muster roll/vouchers were fake.

Charge No. 7.—This charge is proved in toto.

The allegations made in Charge No. 1 and were not proved.

The enquiry report is well reasoned and based on objective evidence/witnesses. On the basis of finding of the Enquiry Officer into the charge Nos. 3, 4, 5, 6 & 7 as mentioned above, the delinquent Pradhan was found guilty of mis-conduct as described under section 146 (1) (b) of the Act and her continuance in the office was, *prima facie*, found to be undesirable in the interest of public.

Therefore, notice under section 146 of the Act was issued on the delinquent Pradhan calling upon her as to why she should not be removed from the office of the Pradhan and also as to why she should not be disqualified for a period of six years to be elected as office bearer of a Panchayat under the Act.

In response to this notice, she filed reply gist of which is tersely recorded as follows:—

- (1) *Regarding Charge No. 3.*—The delinquent Pradhan while admitting that the amount was withdrawn by her husband has rushed to conclude that this is not mis-conduct or illegality or irregularity.
- (2) *Regarding Charge No. 4.*—It has been said by the delinquent Pradhan that the letter of Block Development Officer has not been referred to in the enquiry report. Then again she has submitted that so far as the order of the B. D. O. was concerned, it was duly replied to and action thereafter was taken for the construction of Community Centre, Dabrera.
- (3) *Regarding Charge No. 5.*—It has been said that *vide* resolution of the Panchayat, it was specifically resolved that the member of the Ward where the work was to be done would be in-charge and he/she will be responsible for all types of works. Therefore, the delinquent Pradhan was not responsible for creating fake vouchers and embezzling the amount of such vouchers.
- (4) *Regarding Charge No. 6.*—It has been stated that since there is discrepancy in the total amount, the charge does not stand. Moreover, the work was got done by the Panchayat of the ward, and the bills/vouchers were also prepared by said Panch pursuant to the authorization by the Panchayat to do so through resolution.
- (5) *Regarding Charge No. 7.*—It has been said that the delinquent Pradhan was shown copy of the Audit Report in the Panchayat and she kept that there only and it was for the Secretary to make necessary compliance of the Audit Report.

Finally, the delinquent Pradhan has averred that she could not be removed for the charges referred to above under Section 146 of the Panchayati Raj Act.

It may be mentioned with regard to Charge No. 3, viz-a-viz, the reply of the delinquent Pradhan that the Panchayat/Sabha funds cannot be drawn/handled by any individual other than either the Pradhan himself herself or the Gram Panchayat Avam Vikas Adhikari (Panchayat Secretary) or any member of Panchayat specifically authorized by the Panchayat. The undisputed fact that the amount was withdrawn by the husband of the

7. That the said Pradhan did not keep the Audit Notes in the Panchayat records, which cause non-compliance of the serious objections raised by the Audit Agency. The concerned GPVA has corroborated in his statement that the said Audit notes have not been returned despite repeated requests. This shows that the said Pradhan has not reconciled the audit objections and misused the funds of G. P.

The enquiry into charges was conducted under section 146 of the H. P. Panchayati Raj Act, 1994. On the basis of enquiry report and material on record, the following things came out against the delinquent Pradhans:—

Charge No. 3.—The enquiry officer has concluded that this charge is proved. Moreover it has also been proved that Shri Saligram husband of the Pradhan with draw Rs. 27000/- from Punjab National Bank Lambloo. Therefore the proof is fortified.

Charge No. 4. This charge has been proved to the delinquent Pradhan is guilty of not obeying the legal orders of Block Development Officer. By not starting the work and not returning the money, she put hurdles in the construction of Community Centre Dabrera. The said Pradhan has neither obeyed the legal order of Block Development Officer nor did she write back to Block Development Officer clearing the position.

Charge No. 5.—This charge also stands proved to the extent that the Pradhan has shown payment of Rs. 1425/- *vide* voucher No. 44 dated 27-3-1997 and Rs. 2400/- against voucher No. 43 dated 27-10-97 in favour of Shri Jeet Ram s/o Shri Khiyali Ram, for carriage of stone and sand. These receipts have been passed by the delinquent Pradhan, but actually no payment was received by said Shri Jeet Ram.

Charge No. 6.—With regard to this charge, the Enquiry Officer has reported that all the persons to whom the payment of Rs. 13301/- were shown as made were not produced as witnesses. Therefore, he was not in a position to give his finding regarding whole amount. However, it has been proved that the following payments are fictitious and were never made to the person concerned, as such persons never worked during the period against the works for which payments have been shown:—

Sl. No.	Voucher No.	Name of person	Amount
1	2	3	4
1.	9 of 31-7-96	Jogi Ram s/o Shri Ghungar Ram	Rs. 675

delinquent Pradhan goes sufficiently to prove that there was indulgence of the husband of the said Pradhan in the working of the Panchayat and such indulgence was in the serious businesses like handling of Sabha funds which is exclusive domain of Panchayat. The inescapable corollary is that there was tacit approval of the Pradhan for such indulgence. Therefore, this act of the said Pradhan negates the very principle of democracy at grass root level and it is not only a misconduct, but also gross violation in the discharge of her duties.

Reply to the delinquent Pradhan with regard to the letter of the Block Development Officer is an afterthought. The contention made herein should have been made by her before the Enquiry Officer. Therefore, her version cannot be accepted as such.

With regard to reply into the charge No. 5, the delinquent Pradhan is only passing on the buck. The fact remains that the fictitious vouchers were jointly passed by the Pradhan as well as the wardmember and they have been jointly held responsible for such forgery. This is a matter of record and there is clear statement of the purported recipient that he never received such amount and no more evidence is required to prove this part of charge.

With regard to charge No. 6, the contention of discrepancy in the total amount does not help the averments made by the delinquent Pradhan. It is again a matter of record and there is specific statements of the purported recipients that they did not receive the amount. Although the vouchers are signed and passed by both Pradhan and the Panch, but before passing the payment, the Pradhan should have checked up the veracity of the vouchers and also the work done on the spot. Making payment is primarily the responsibilities of the Pradhan and when the vouchers are attested the presumption is that the payment is made before attestor.

With regard to her reply into charge No. 7, it is mentioned that the enquiry officer has reported that not only that the Panchayat Secretary asked the delinquent Pradhan to return Audit Report but also there were letters from District Panchayat Officer on record making the similar letters from District Panchayat Officer on record making the similar request and also that the discussion regarding this in the Panchayat meeting held on 11-7-99 did not yield any result. The delinquent Pradhan did not defend this charge at the time of enquiry before the Enquiry Officer despite ample opportunity being provided to her. Therefore, her contention that she did not receive the report of the Audit cannot be accepted at this stage. Was it so she should have replied to the communication of the District Panchayat Officer and also should have brought it to the notice of the members in the Panchayat Meeting of dated 11-7-1999.

Now the question of determination is as to whether the proven charges against said Pradhan constitute the mis-conduct as defined under Section 146 (b) of the Act or not. The contention of the delinquent Pradhan is that the allegation mentioned in the charge against her do not constitute "mis-conduct".

The mis-conduct has been explained as follows in Section 146 itself:—

Explanations.—For the purpose of this sub-section, mis-conduct shall include:—

(a) any action which adversely affects:—

- (i) the sovereignty, unity and integrity of India ; or
- (ii) the harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of State transcending religious, linguistic, regional, caste or section diversities ; or
- (iii) the dignity of women; or

(b) gross negligence in the discharge of the duties under this Act ;

The word "shall include", go to conclude that the mis-conduct as defined in the Section includes many other Acts. The charges proved against the delinquent Pradhan range from financial mis-appropriation, to disobedience of lawful orders and allowing indulgence of closed relative into the serious business of the Panchayat. Such act on the part of a person holding public and responsible office is definitely a mis-conduct and the delinquent Pradhan is guilty of misconduct.

For the reasons recorded heretofore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Section 146 (1) of the Panchayati Raj Act, 1994, is pleased to remove said Smt. Sneha Lata, Pradhan (suspended) Gram Panchayat, Lambloo, Block Hamirpur, District Hamirpur forthwith. The Governor Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under Act *ibid*, is further pleased to order the dis-qualification of said Smt. Sneha Lata, Pradhan (Under suspension), District Hamirpur, Himachal Pradesh for a period of six years to be elected as office bearer of a Panchayat under this Act.

These orders shall become into force with immediate effect.

Shimla-9, the 13th December, 2000

No. PCH-HA (5) 68/99.—That Smt. Sneha Lata, Pradhan Gram Panchayat Lambloo, Development Block Hamirpur, District Hamirpur was placed under suspension for the following allegations:

1. That Smt. Sneha Lata, Pradhan remains out of the Sabha Area except on days fixed for meetings Gram Panchayat, which causes grave inconveniences to the public in getting their works done. The G. P. has passed a Resolution No. 2 dated 26-5-1999 to this effect. That the said Pradhan does not take other members into confidence and decides issues at her own whims. Neither the said Pradhan puts forth the Dak of the Panchayat nor does she maintain it in the records. The G. P. has quoted an instance of Shri Mulak Raj s/o Shri Durga Dass. This fact has also been corroborated by the statement made by the said Pradhan during preliminary inquiry wherein she insisted that she would work at her own way though complaint can be made against her for it. This fact proves that Smt. Sneha Lata is misusing the powers, responsibilities of the post of Pradhan, besides neglecting the provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.
2. That the said Pradhan decides judicial cases at the instance of her husband and her husband interferes in the proceedings of the G. P. which was objected to by all the members of the G. P. Her husband also advises her for imposing fines etc. The fines imposed on accused are not they received any payment. Hence, the said Panch has embezzled following amounts by preparing fake bills/vouchers.—

Sl. No.	Name of the labourer	Voucher No. & date	Description
1	2	3	4
1.	Shri Nek Ram (member of construction committee).	40/26-10-97 05/27-7-97 09/31-7-96 10/13-8-96 11/31-3-97	Muster roll of October, 1997. 8 bags of cement Muster roll of July, 98. Muster roll of August, 96. Muster roll of March, 1997.
2.	Smt. Geeta Devi (member of Construction committee)	15/11-8-87 16/11-8-97	14 bags of cement Muster roll of June, 1997.

1	2	3	4
	19/15-9-97	2 bags of cement	
	20/15-9-97	22 trips of house charges.	
	21/15-9-97	Muster roll of July, 1997.	
	38/26-10-97	5 bags of cement	
	39/26-10-97	17 bags of cement	
	40/26-10-97	Muster roll of October, 1997.	
	05/27-7-96	8 bags of cement	
	10/13-9-96	Muster roll of Aug., 96.	
	11/31-3-97	Muster roll of March, 97.	
3. (i) Shri Praveen Kumar, Village Thankari.	15/1-8-97	14 bags of cement	
(ii) Meera Devi w/o Shri Vidhi Chand, Village Thankari.	19/15-9-97	2 bags of cement	
(iii) Roshan Lal s/o Shri Chaudhari Ram, Village Thankari.	20/15-9-97	22 bags of cement	
	21/15-9-97	Muster roll of July, 97.	
	38/26-10-97	5 bags of cement	
	39/26-10-97	17 bags of cement	
	05/27-7-96	8 bags of cement	
	09/31-7-96	Muster roll of July, 96.	
	11/31-3-98	Muster roll of March, 97.	
4. Shri Hoshnaki Ram s/o Shri Laturia Ram, Village Thankari.	19/15-9-97	2 bags of cement	
	16/15-9-97	22 trips of house for bolders.	
	21/15-9-97	Muster roll of July, 97.	
	38/26-10-97	5 bags of cement	
	05/27-7-96		
5. Shri Swatanter Kumar s/o Shri Hem Raj	15/11-8-97	14 bags of cement	
	16/11-8-97	Muster roll of January, 97.	
	19/15-9-97	2 bags of cement	
	20/15-9-97	22 trips of hours. for bolders.	
	21/15-9-97	Muster roll of July, 97.	
	10/13-8-96	Muster roll of August, 96.	
	11/31-3-97	Muster roll of March, 97.	

The enquiry into charges was conducted under Section 146 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994. On the basis of enquiry report and material on record, the following things came out against the delinquent Panch :-

Charge No. 1.—This charge stands proved to the extent that the said Panch in connivance with Pradhan has shown payment of Rs. 1425/- vide voucher No. 44, dated 27-3-1997 and Rs. 2400/- against voucher No. 33 dated 27-10-97 in favour of Shri Jeet Ram s/o Shri Khiyali Ram, for carriage of stone and sand. These receipts have been passed by the delinquent Panch/Pradhan, but actually no payment was received by said Shri Jeet Ram.

Charge No. 2.—With regard to this charge, the Enquiry Officer has reported that all the persons to whom the payment of Rs. 13301/- were shown as made were not produced as witnesses. Therefore, he was not in a position to give his finding regarding whole amount. However, it has been proved that the following payments are fictitious and were never made

to the person concerned, as such persons never worked during the period against the works for which payments have been shown :-

Sl. No.	Voucher No.	Name of person	Amount
1	2	3	4
1.	9 of 31-7-1996	Jogi Rams/o Shri Ghungar Ram	675
2.	16 of 11-8-1997	-do-	675
3.	16 of 18-8-1997	Pravin Kumar s/o Shri Dina Nath.	405
Total Rs.			1,755

In addition to this, the Enquiry Officer has also pointed out that some of the signatures of members of Development Committee on the muster roll/vouchers were fake.

The enquiry report is well reasoned and based on objective evidence/witnesses. On the basis of finding of the Enquiry Officer into the charge Nos. 1 & 2 as mentioned above, the delinquent Panch was found guilty of misconduct as described under section 146 (1) (b) of the Act and her continuance in the office was, *prima facie*, found to be undesirable in the interest of public.

Therefore, notice under section 146 of the Act was issued on the delinquent Panch calling upon her as to why she should not be removed from the office of Panch and also as to why she should not be disqualified for a period of six years to be elected as office bearer of the Panchayat under the Act.

In response to this notice she filed reply, gist of which is tersely reproduced as under :-

Regarding these charges, she has stated that the vouchers/bills were prepared by Smt. Sneha Lata, Pradhan and her husband at their residence and that she was illiterate and she only put signatures at the instance of the Pradhan and her husband whereas she did not know what were the contents of the paper on which she had put her signature. She also has contended that the payments are made only after the Pradhan puts the signature and the Pradhan is responsible for making all payments.

It may be mentioned with regard to charge No. 1 & 2 that the said Panch can not take refuge in her ignorance or illiteracy. Moreover, the resolution of the Gram Panchayat entrusted her with the work relating to her ward. Natural conclusion is that she was having knowledge of the work done by different modes and by different persons. Before signing vouchers it was her duty to inquire that the vouchers were correct. She cannot take shelter that the payment could be made through the signatures of the Pradhan only. Since, the said work done was relating to her ward and she was primarily responsible to get the work done and to see that proper account of the expenditure is made. By creating and keeping false vouchers she is equal partner in the design.

Now the question for determination is as to whether the proven charges against said Panch constitute the misconduct as defined under Section 146 (b) of the Act or not.

The misconduct has been explained as follows in Section 146 itself :-

Explanation.—For the purpose of this sub-section misconduct shall include :-

(b) any action which adversely affects :-

(iv) the sovereignty, unity and integrity of India; or

(v) the harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of

State transcending religious, linguistic, regional, caste or section diversities; or
(vi) the dignity of women; or

(b) gross negligence in the discharge of the duties under this Act ;

The word "shall include", go to conclude that the misconduct as defined in the Section includes many other acts. The charges proved against the delinquent Panch relate to financial misappropriation. Such act on the part of a person holding public and responsible office is definitely a misconduct and the delinquent Panch is guilty of misconduct.

For the reasons recorded heretofore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Section 146 (1) of the Panchayati Raj Act, 1994,

is pleased to remove said Smt. Urmil, Panch (Suspended), Gram Panchayat, Lambloo, Block Hamirpur, District Hamirpur forthwith. The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under the Act *ibid*, is further pleased to order the dis-qualification of said Smt. Urmil, Panch (Under Suspension), Gram Panchayat Lambloo, Development Block Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh for a period of six years to be elected as officer bearer of a Panchayat under this Act.

These orders shall become into force with immediate effect.

By order,

SUDRIPTO ROY,
Commissioner-cum-Secretary.

भाग-5—व्यक्तिगत अधिसूचनाएं और विज्ञापन

व अदालत जनाब कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर
हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेश कुमार सुपुत्र श्री निक्का राम, निवासी गांव धारटोह,
तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि 3 प्र 0) सायल ।

बनाम

ग्राम जनता उत्तरवादी ।

इरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम,
1969.

उपरोक्त मकदमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री सुरेश कुमार सुपुत्र
श्री निक्का राम, निवासी धारटोह, तहसील सदर, जिला बिलासपुर
(हि 0 प्र 0) ने इस न्यायालय से गुजारिश की है कि उसकी स्वयं की जन्म
तिथि, 1-6-1982 है लेकिन पंचायत अभिलेख में 1-5-1985 दर्ज है
जो कि गलत है ।

अतः ग्राम जनता को बजरिया राजपत्र में सूचित किया जाता है कि
अगर किसी को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर या एतराज हो तो
वह दिनांक, 22-3-2001 को असातन व वकालतन इस न्यायालय में
प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा उप-
रोक्त आवेदक श्री सुरेश कुमार सुपुत्र श्री निक्का राम, निवासी धारटोह
की जन्म तिथि, 1-5-1985 पंचायत अभिलेख में परिवर्तन करने बारे
आदेश जारी कर दिया जाएगा ।

आज दिनांक 8-3-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से
जारी हुआ ।

मोहर ।

के 0 आर 0 सहजल,
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
सदर, बिलासपुर (हि 0 प्र 0) ।

व अदालत श्री देव राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री विनय दास सुपुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी गांव बटेड़ उपरली,
तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधि-
नियम, 1969.

उपरोक्त मकदमा अदालत हुआ में प्रार्थी श्री विनय दास सुपुत्र
श्री गोबिन्द राम, निवासी बटेड़ उपरली, तहसील सदर, जिला

बिलासपुर ने प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के का नाम अंकित
पुष्पेन्द्र कुमार का जन्म 1-8-1995 को हुआ है परन्तु अमानता-
बश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरमाणा में दर्ज नहीं
करा सका है ।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता
है कि इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक,
26-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित सदर
तहसील में असातन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता
है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की
सुरत में प्रार्थना-पत्र श्री विनय दास पर नियमानुसार कार्यवाही
की जाएगी ।

आज दिनांक 12-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत
द्वारा जारी किया गया ।

मोहर ।

देव राज शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी सदर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

In the Court of Shri R. S. Jasrotia, SDO (Civil)-cum-
Marriage Officer, Nahan, District Hamirpur,
Himachal Pradesh

In the matter of : Sunil Kumar Next date of
with hearing
Radha Sharma 24-3-2001

Application under section 16 of the Special Marriage
Act, 1954 as amended by Act of 1976.

Sunil Kumar s/o Shri Rattan Chand, r/o Village
Jangli, P. O. Sera, Tehsil Nadaun, District Hamirpur,
Himachal Pradesh Bridgroom.

Radha Sharma d/o Shri Kishori Lal, r/o House No.
98, Friends Avenue, Street No. 3, Tungwala, Majitha
Road, Amritsar (Punjab) Bride.

To The General Public.

Whereas Shri Sunil Kumar and Radha Sharma stated
before undersigned on 23-9-2000 that a marriage
ceremony between them will be performed. They
further requested that their marriage may be regis-
tered under above mentioned act.

Notice in respect of general public is hereby issued.
If any one has any objection to the above marriage
he/she can submit his/her objection in person or
through his/her representative on or before 24-3-2001
in my Court otherwise marriage would be registered.

Given under my signature and office seal on this 16th day of February, 2001.

Seal.

R. S. JASROIA,
S. D. O. (Civil)-cum-Marriage Officer,
Sub-Div. Nadaun,
District Himachal Pradesh (H. P.).

बे अदालत श्री अमर सिंह चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

विषय.—मकफूद-उल-खवरी श्री विश्वनाथ पुत्र सेरू, वासी धलू, तप्पा जलाड़ी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर का इंतकाल नं० 53, मुहाल धलू, मौजा जलाड़ी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर।

बनाम

(1) श्रीमती केसरी देवी विधवा व (2) संजीव कुमार, (3) राजीव कुमार पुत्र व (4) मन्तोप कुमारी, (5) अनीता कुमारी, (6) रेखा कुमारी पुत्रियां विश्वनाथ पुत्र सेरू, वासी धलू, मौजा जलाड़ी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषय पर इस्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वनाथ पुत्र सेरू, वासी धलू, मौजा जलाड़ी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश अगस्त 15 वर्ष से लापता है। अगर विश्वनाथ कहीं जीवित हो तो वे हमारी अदालत में 26-3-2001 के पहले असादन या बकालतन पेश हो सकता है। क्योंकि उसके मरने/जाने की कोई खबर नहीं है अन्यथा उपरोक्त इन्तकाल मकफूद-उल-खवरी 53, बरास्त वहक वारमान कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 24-2-2001 को इस्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

अमर सिंह चौहान,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नादौन, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री लाल बोर राय, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं०.—1-2-3-4-5/2001.

उमवाल मुकद्दमा: तकसीम भूमि

तारीख पेशी: 29-3-2001.

1. अमर सिंह, 2. देश राज पुत्रान, 3. विशाली देवी विधवा वामाराम, 4. सुखलाल, 5. सुरेश पुत्रान, 6. मंगला पुत्री मन्तलवी, वासी मुहाल कलरू, मौजा वूसल, तहसील बड़ोह, वादीगण।

बनाम

प्रोतो पुत्र गरीब, वासी मुहाल कलरू, मौजा वूसल, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादी।

विषय.—मुकद्दमा तकसीम बावत अराजी खाता नं० 11-2 मुहाल बड़ोह, मौजा जन्दाह व खाता नं० 32-26 मुहाल कलरू व खाता नं० 5, मुहाल वूसल, मौजा वूसल, तहसील बड़ोह।

उमवाल मुकद्दमा उपरोक्त में प्रतिवादी प्रोतो पुत्र गरीब के बारे में तामील कनिश्ठा व ग्राम वासियों से पता चला है कि वह कई वर्षों से साधु बन गया है इसलिए साधारण ढंग से तामील किया जाना मुश्किल है लिहाजा इस इस्तहार द्वारा प्रतिवादी को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 29-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असादन या बकालतन हाजर अदालत आकर पेशी मुकद्दमा करें। हाजर न आने की सूत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-2-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

मोहर।

लाल बोर राय,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा।

व अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

अमर सिंह पुत्र चहड़ू, वासी मुहाल पीहड़ी, मौजा खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम की दफ्ती वारे।

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

उपरोक्त विषय के मन्दर्भ में प्राचीन अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि कागजान माल मुहाल पीहड़ी व भलेलू, मौजा सहोदय में उसका नाम अमर सिंह की बजाये अमरने दर्ज हुआ है जो कि गलत है। पंचायत रिकार्ड के परिवार रजिस्टर के मता-विक अमर सिंह पुत्र चहड़ू दर्ज है। अतः नाम की दफ्ती की जावे।

इस इस्तहार भजट द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को इस नाम की दफ्ती वारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2001 को सुबह 10.00 बजे अदालत में हाजर आकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री हरि चन्द पुत्र बंगाली राम, निवासी जंजर, मौजा मझी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा प्रार्थी।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र दफ्ती नाम हरिया के स्थान पर हरि चन्द के मन्दर्भ में।

श्री हरि चन्द पुत्र बंगाली राम ने इस अदालत में उपरोक्त मन्दर्भ में प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया है कि उसका नाम राजस्व भू-प्रभिलेख में हरिया दर्ज है जबकि वास्तव में उसका नाम हरि चन्द है, उसे दफ्ती किया जावे।

अतः मवेसाधारण को इस इस्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असादन या बकालतन हाजर होकर पेशी कर सकता है और अपने एतराज पेश कर सकता है तथा निश्चित तिथि पर कोई आपत्ति न प्रस्तुत करने पर एक तरफा फैसला कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 29-01-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-,
कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी,
खुण्डिया, जिला कांगड़ा।

व अदालत जनाब श्री मनोहर लाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री बन्नी राम पुत्र श्रीमती रामी देवी विधवा धनू, निवासी
भरोल बजरिया मुखार ग्राम श्री नारायण सिंह पुत्र श्री धनू,
निवासी भरोल, मौजा सोहलदा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश प्राथीगण।

बनाम

1. महिन्दर सिंह, 2. शेर सिंह, 3. ओंकार सिंह, 4. भोम प्रकाश,
5. पवन कुमार पुत्र व 6. श्रीमती राणो देवी पुत्री तथा
7. श्रीमती आनो देवी विधवा जमोत, 8. अमर सिंह, 9. बन्नी
राम पुत्रान श्री फकीर, 10. श्री प्रेम सिंह, 11. संसार चन्द,
12. स्वर्ण सिंह पुत्रान व 13. श्रीमती स्नेहलता, 14. श्रीमती सिरमता
देवी पुत्रियां व 15. श्रीमती बिद्या देवी विधवा मिचिल, 16. जफड़
उर्फ पंजाब सिंह, 17. गोरख राम पुत्र जोधा, 18. श्रीमती व्यासो
देवी, 19. गिरधारी लाल पुत्र बैन्त, सभी निवासस्थान भरोल,
मौजा सोहलदा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
प्रतिवादीगण।

दरखास्त बराये तकसीम अराजी खाता नं० 57, खतौनी नं०
163-164, खमरा नं० 261-262-263-260-264
किता 5, रक्बा तादादी 0-05 99 है० मीटर बाक्या
महाल भरोल, मौजा सोहलदा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन भेजे गये परन्तु
प्रतिवादीगण नौकरी पेशा या शादी शुदा होने के कारण समनों को
तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकी अतः बजरिया इशतहार
उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक
23-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में असालतन
या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। अन्यथा गैर
हाजिरी की सूरत में उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में
लाई जावेगी।

आज दिनांक को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में
जारी हुआ।

मोहर।

मनोहर लाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री मनोहर लाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

उनवान मुकद्दमा : तकसीम भूमि तारीख पक्षी 22-3-2001

श्री बन्नी लाल पुत्र श्रीनाथ आदि, निवासस्थान ज्वाली, जिला
कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

1. श्री बहमा उर्फ चमन लाल पुत्र गुसांज, 2. रूप लाल, 3.
हरनाथ चन्द, 4. जैन सिंह पुत्रान श्रीमती परन्तु पुत्री गुसांज, 5.
नेष्टा देवी, 6. सन्तोष कुमारी पुत्री परन्तु, निवासस्थान टीका व
मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

दरखास्त बराये तकसीम अराजी खाता नं० 238 खतौनी नं०
691 ता 701, खमरा नम्बरान 1635, 1683, 2156, 1637,
1638, 1644, 1689, 1693, 2152, 2162, 2169, 2154,
1643, 1685, 1587, 1688, 2153, 2160, 1686, 1638,
1641, 2155, 2157, 1640, 1690, 1638, 1642, 1684,
1692, 2151, 2158, 2166, 1691, 2159, 2163, 2164,
2165, 2150, किता 38, रक्बा तादादी 1-77-98 है० बाक्या
महाल कैहरिया, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल
प्रदेश।

उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन भेजे गये परन्तु
प्रतिवादीगण नौकरी पेशा या शादी शुदा होने के कारण समनों को
तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकी। अतः बजरिया इशतहार
उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 22-3-2001
को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर
आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में
उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई जावेगी।

आज दिनांक.....को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत
से जारी हुआ।

मोहर

मनोहर लाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा
(हि० प्र०)।

व अदालत श्री मनोहर लाल, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

उनवान मुकद्दमा : तकसीम भूमि

1. बाबू राम, 2. बन्नी लाल पुत्रान नाथ, 3. मनजीत राय,
4. रणजीत कुमार, 5. सुरजीत कुमार, 6. नसीब चन्द, 7. सून्चा
सिंह पुत्रान व 8. राज कुसारी विधवा राम चन्द उर्फ कर्म चन्द,
9. बलवीर सिंह पुत्र, 10. रोशनी देवी, 11. काला देवी, 12.
निर्मला देवी पुत्रियां, 13. सावित्री देवी विधवा जैसी राम, 14.
किशन चन्द पुत्र बाबू राम, 15. पंजाब सिंह, 16. रूपकू राम
पुत्रान दूतो, 17. स्वर्ण सिंह, 18. वीर सिंह, 19. फकीर सिंह
पुत्रान केहर चन्द, निवासस्थान टीका व मौजा ज्वाली, तहसील
ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्राथीगण।

बनाम

1. बहमा उर्फ चमन लाल पुत्र गुसांज, 2. रूप लाल, 3.
करतार सिंह, 4. जैन सिंह पुत्रान, 5. श्रेष्ठा देवी, 6. सन्तोष
कुमारी पुत्रियां परन्तु पुत्री गुसांज, 7. हरबंस लाल पिता सुरेश
कुमार, निवासस्थान टीका व मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा
(हि० प्र०)। प्रतिवादीगण।

दरखास्त बराये तकसीम अराजी खाता नं० 37, खतौनी नं०
72 से 81, खमरा नं० 317, 383, 391, 320, 324, 353,
367, 388, 389, 319, 456, 390, 392, 366, 387,
323, 362, 385, 321, 318, 326, 357, 358, 359,
363, 386, 394, 316, 322, 368, 395, 325, 364,
382 (किता 34), रक्बा तादादी 0-60-30 है० बाक्या महाल
व मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बकाये
वरुण जमवन्दी माल 1994-95।

उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन भेजे गए परन्तु
प्रतिवादीगण नौकरी पेशा या शादी शुदा होने के कारण समनों को
तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकी। अतः बजरिया इशतहार
उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक
22-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में असालतन या
वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। अन्यथा गैर
हाजिरी की सूरत में उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में
लाई जावेगी।

आज दिनांक.....की हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मनोहर लाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा,
(हि० प्र०)।

आज दिनांक 13-2-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
कल्पा स्थित रिकॉम पिथो,
जिला किन्नोर (हि० प्र०)।

व अदालत श्री अंकार सिंह जरियाल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, ज्वाली, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

व न्यायालय श्री परम देव शर्मा, उप-पंजीकाध्यक्ष, उप-तहसील बलदाड़ा, जिला मण्डी

व मुकद्मा :

मुकद्मा नं० नाम की दस्तवी तारीख पेशी 27-3-2001

कशमीर सिंह पुत्र श्री सन्तू राम, निवासी कसमैला, इलाका हटली, उप-तहसील बलदाड़ा, जिला मण्डी (हि० प्र०) .. प्राप्ती।

जगत राम उर्फ बरड़ू राम

बनाम

बनाम

ग्राम जनता

.. करीकदम।

ग्राम जनता

दरखास्त बगर्ज पंजीकरण किए जाने वसीयत नामा।

श्री जगत राम पुत्र श्री नकेलू राम, साकन हरसर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि मेरा नाम जगत राम उर्फ बरड़ू राम कामजात माल में गलत दर्ज हुआ है जिसकी मैं दस्तवी करवाना चाहता हूँ। कामजात माल में सायल का नाम जगत राम उपनाम बरड़ू राम दर्ज किया जावे।

उपरोक्त प्राप्ती ने हमारे समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसके बाप मन्तू राम पुत्र धुगर, निवासी कसमैला, उप-तहसील बलदाड़ा, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने एक वसीयत नामा अपने घर पर अपने दो लड़कों मन्तूजी जगदीश चन्द, कशमीर सिंह पुत्र व श्रीमती रजो देवी पत्नी श्री सन्तू राम, निवासी कसमैला के नाम पर निष्पादित करवाया है तथा उक्त वसीयतनामा को दर्ज रजिस्टर किया जावे सन्तू राम वूसी दिनांक 3-8-1997 को स्वर्ग मिथार गया है जिस वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कसमैला द्वारा जारी किया गया है।

अतः बजरिया इस्तहार हजा ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वसीयत नामा को तस्दीक एवं दर्ज रजिस्टर होने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-3-2001 को प्रातः 10-00 बजे या उसके बाद एक महीना के अन्दर उपस्थित न्यायालय में आकर पेश करें अन्यथा कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से आज दिनांक 24-2-2001 को जारी हुआ है।

मोहर।

परम देव शर्मा,
उप-पंजीकाध्यक्ष,
उप-तहसील बलदाड़ा, जिला मण्डी।

व अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रामीण), शिमला जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री चेत राम पुत्र स्व० श्री मस्त राम, निवासी गांव धुंग, पी०ओ० रोडी, तहसील एवं जिला शिमला, (हि० प्र०)।

बनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बावत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री चेत राम ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके बेटे अजय का नाम तथा जन्म तिथि 5-12-1995 उनकी ग्राम पंचायत नेरी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा रखी है। अतः अब दर्ज की जाए।

अतः इस अदालती इस्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक के बेटे का नाम व जन्म तिथि उनकी ग्राम पंचायत नेरी के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति

अतः इस इस्तहार द्वारा हर खास व ग्राम को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 27-3-2001 को प्रातः 10-00 बजे अदालत में पेश करें अन्यथा कामजात माल में नाम की दस्तवी के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-2-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

अंकार सिंह जरियाल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
ज्वाली कांगड़ा।

व अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी कल्पा स्थित रिकॉम पिथो, जिला किन्नोर, हिमाचल प्रदेश

जनक राज बनाम ग्राम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जनक राज पुत्र श्री सनम दोरजे, निवासी ग्राम सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नोर (हि० प्र०) ने इस अदालत में दरखास्त प्रस्तुत की है कि उनके तथा उसके निम्न परिवार सदस्य का निम्न जन्म तिथि ग्राम पंचायत सापनी, तहसील सांगला के अभिलेख में पंजीकृत नहीं है अतः इस विषय पंजीकरण हेतु सम्बन्धित पंचायत को आदेश जारी करने की कृपा करें।

क्रमांक	नाम	प्राप्ती के साथ सम्बन्ध	जन्म तिथि
5-5-1998	ज्योती	पुत्री	5-5-1998

अतः इस इस्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण हेतु कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 26-3-2001 को सुबह 10-00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर प्रस्तुत करे वरना एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे।

हो तो वह अपना आपतिनामा दिनांक 29-3-2001 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम व जन्म तिथि उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ है।

मोहर।

राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा०),
शिमला, जिला शिमला, (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रामीण), शिमला जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री श्यामा नन्द पुत्र स्व० श्री मुनू राम, निवासी गांव दोहाई, पी०ओ० डूबलू, तहसील व जिला शिमला (हि० प्र०)।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री श्यामा नन्द ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी बेटी मनीषा कुमारी का नाम तथा जन्म तिथि 2-6-1995 उनकी ग्राम पंचायत जनेड़घाट के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है। अतः अब दर्ज की जाए।

अतः इस अदालती इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक की बेटी का नाम व जन्म तिथि उनकी ग्राम पंचायत जनेड़घाट के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपतिनामा दिनांक 29-3-2001 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम व जन्म तिथि उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ है।

मोहर।

राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा०),
शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रामीण), शिमला जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री श्रीम प्रकाश पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी गांव सुजाना, पी०ओ० चनोग, तहसील एवं जिला शिमला (हि० प्र०)।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री श्रीम प्रकाश ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी बेटी कुमारी वनीता का नाम व जन्म तिथि 6-4-1996 उनकी ग्राम पंचायत चनोग के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है। अतः अब दर्ज की जाए।

अतः इस अदालती इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक की बेटी का नाम व जन्म तिथि उनकी ग्राम पंचायत चनोग के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपतिनामा दिनांक 29-3-2001 तक

या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम व जन्म तिथि उनकी ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-2-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा०),
शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री राजेश शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रामीण) शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री कुलवन्त सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव भलोग, पी०ओ० तारा देवी, तहसील व जिला शिमला (हि० प्र०)।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री कुलवन्त सिंह ने इस अदालत में एक आवेदन-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती मन्दर कौर का नाम व शादी तिथि 19-4-2000 उसकी ग्राम पंचायत रझाना के अभिलेख में दर्ज नहीं कर रखी है।

अतः इस अदालती इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उक्त आवेदक की शादी की तिथि उनकी ग्राम पंचायत रझाना के अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह अपना आपतिनामा दिनांक 29-3-2001 तक या उससे पूर्व इस अदालत में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सचिव सम्बन्धित ग्राम पंचायत को नाम व शादी की तिथि उनकी पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

राजेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ग्रा०),
शिमला, जिला शिमला,
(हि० प्र०)।

In the Court of Sh. Kirpa Ram Sharma, Executive Magistrate Nerwa, Distt. Shimla (H. P.)

In the Matter of :

Smt. Kaushalya Devi wd/o Shri Kirpa Ram, R/o village Ghala, Pargana, Chandlog Sub-Teh. Nerwa, Distt. Shimla (H. P.)
..Petitioner.

Vs.

General Public

..Respondant.

Application under the provisions of Death and Birth Registration Act for the registration of the applicant.

To

The General Public.

Whereas the above mentioned petitioner has filed an application u/s 13(3) of the Birth and Death Registration Act, for seding order to Secy. Gram Pan-chayat Deyia Dohi, Sub-Teh. Nerwa, Distt. Shimla (H. P.) for the registration of date of birth her son namely Ankesh born on 7-3-1998 at village Ghalla, Sub-Teh. Nerwa, Distt. Shimla (H.P.).

Hence this proclamation is hereby issued to the general public and kith and kins to file their objections, if any, in this court on or before 27-3-2001 either personally or through an authorised agent failing which the application shall be heard and allowed in favour of above petitioner.

Given under my hand and the seal of the court this 16th day of February, 2001.

Seal. KIRPA RAM SHARMA,
Executive Magistrate,
Nerwa, District Shimla.

व अदालत श्री बालक राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुझहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती हनुवरी देवी पत्नी श्री मधू राम, निवासी कराली, तहसील
रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधि-
नियम, 1969.

श्रीमती हनुवरी देवी पत्नी श्री माधू राम, निवासी कराली, तहसील
रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में गुजारिश
की है कि उसके पीत विजय कुमार सुपुत्र नन्द लाल को जन्म
तिथि पंचायत रिकार्ड में समय पर दर्ज न करवा सकी । अब
करवाना चाहती है ।

अतः इस इशतहार द्वारा हर खाम व ग्राम को सूचित किया जाता
है कि यदि किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में उजर व एतराज हो तो
वह दिनांक 25-3-2001 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे अदालत
या वकालत हाजर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा पंचायत
रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किए जायेंगे ।

आज दिनांक 17-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर
अदालत से जारी किया गया ।

मोहर । बालक राम नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुझहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश ।

व अदालत श्री बालक राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर
बुझहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री नन्द लाल पुत्र श्री तुलसी राम, साकन ग्राम देवला छात्र,
तहसील व जिला बिलासपुर हाल ग्राम झाकड़ी, तहसील रामपुर,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
अधिनियम, 1969.

श्री नन्द लाल पुत्र श्री तुलसी राम, ग्राम देवला छात्र, तहसील
व जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश हाल ग्राम झाकड़ी, तहसील
रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में गुजारिश
की है कि उसकी पुत्रियां सोना कुमारी व बबली कुमारी का जन्म
ग्राम पंचायत क्षेत्र धार गौरा, ग्राम झाकड़ी में हुआ है । पंचायत
रिकार्ड धार गौरा में पुत्रियों का नाम समय पर दर्ज नहीं करवा
सका । अब करवाना चाहता है ।

अतः इस इशतहार द्वारा हर खाम व ग्राम को सूचित किया
जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस तारा उजर व एतराज
हो तो वह दिनांक 25-3-2001 को प्रातः 10 बजे या इससे
पूर्व अदालत या वकालत हाजर अदालत होकर अपना उजर व
एतराज पेश करें अन्यथा पंचायत रिकार्ड में नाम दर्ज करने के
आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 17-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत
से जारी किया गया ।

मोहर । बालक राम नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुझहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश ।

व अदालत श्री बालक राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी
रामपुर बुझहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री अजय सुपुत्र श्री काली दास, निवासी ग्राम रबोली, तहसील
रामपुर बुझहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
अधिनियम, 1969.

श्री अजय पुत्र श्री काली दास, निवासी ग्राम रबोली, तहसील
रामपुर बुझहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में
गुजारिश की है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में नातः रान
दर्ज है जिसे वह तबदील करवा कर अजय दर्ज करवाना चाहता
है ।

अतः इस इशतहार द्वारा हर खाम व ग्राम को सूचित किया
जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस सम्बन्ध में किसी प्रकार
का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-3-2001 को या
इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे अदालत या वकालत हाजर
अदालत होकर पेश करें अन्यथा पंचायत अभिलेख में नाम दस्तवी/
तबदील के आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 17-2-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत
से जारी किया गया ।

मोहर । बालक राम नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुझहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश ।

व अदालत श्री बालक राम नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुझहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री रूप लाल पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी ग्राम झाकड़ी, तहसील
रामपुर बुझहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

बनाम

ग्राम जनता प्रतिवादी ।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
अधिनियम, 1969.

श्री रूप लाल सुपुत्र अर्जुन सिंह, निवासी ग्राम झाकड़ी, तहसील
रामपुर बुझहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में
गुजारिश की है कि उसके पुत्र पंकज की जन्म तिथि समय पर
पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका । अब पुत्र का नाम ग्राम
पंचायत धार गौरा के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता
है ।

अतः इस इशतहार द्वारा हर खास व ग्राम को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस वारा उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-3-2001 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे अनालतन या वकालतन हाजर अदालत हो कर अपना उजर व एतराज पेश करे अन्यथा पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-2-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

बालक राम नंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुझहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री साणू राम पुत्र श्री शोभा राम, निवासी गांव बड़वास, तहसील
पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम,
1969.

श्री साणू राम पुत्र श्री शोभा राम, निवासी गांव बड़वास, तहसील
पांवटा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके बच्चों
का जन्म दिनांक 26-1-92, 25-11-96, 10-2-97 को हुआ था
परन्तु अज्ञानतावश वह उनका जन्म ग्राम पंचायत बड़वास के रिकार्ड
में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता
है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह
दिनांक 26-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हाजिर
स्थित पांवटा में अनालतन या वकालतन हाजर आकर अपने
स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज
प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री साणू राम पर नियमा-
नुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 26-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर
अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डा0 एम0 पी0 सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

व मुकदमा:

श्री सूरत सिंह श्री पुत्र तुलसी राम, निवासी भरली, तहसील पांवटा

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरस्ती नाम।

उपरोक्त मुकदमा उनवान वाना में श्री सूरत सिंह मुपुत्र श्री तुलसी
राम, निवासी भरली मय ब्यान हल्फिया बयानात/प्रार्थना-पत्र दिया है
कि ग्राम पंचायत शिवा के रिकार्ड में उसकी पत्नी व बच्चे नाम ललित
एवं नरेन्द्र गलती से उसके भाई धर्म सिंह के नाम पर दर्ज हो गए है
जबकि उक्त नवदम उसकी परिवार के हैं। इस जनता को दर्स्त
किया जाए।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि
अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह
अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 26-3-2001 से पूर्व अपने
एतराज अनालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित
अवधि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत पर श्री सूरत सिंह
के प्रार्थना-पत्र पर आगामी कार्यवाही कर दी जाएगी।

आज दिनांक 26-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर
अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डा0 एम0 पी0 सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डा-
धिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

डंडू राम पुत्र चाईया, निवासी सठार, तहसील पांवटा, जिला
सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण
अधिनियम, 1969.

डंडू राम पुत्र चाईया, निवासी सठार, तहसील पांवटा ने इस
अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना स्वयं
का जन्म दिनांक 1-1-1954 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश
वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरवोली के रिकार्ड में 1954
दर्ज की गई है जो गलत है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफेत सूचित किया
जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह
दिनांक 28-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हाजिर
पांवटा में अनालतन या वकालतन हाजर आकर दर्ज करा सकता है
निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपरित प्राप्त न होने की सूरत में
प्रार्थना-पत्र श्री डंडू राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 28-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर
अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डा0 एम0 पी0 सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।

ब अदालत डा0 एम0 पी0 सूद (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल
दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

उषा देवी सुपुत्री फिसफू, निवासी डोवरी सालवाला, तहसील
पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधि-
नियम, 1969.

उषा देवी पुत्री फिसफू, निवासी डोवरी सालवाला, तहसील
पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका
स्वयं का जन्म दिनांक 10-8-1978 को हुआ था परन्तु अज्ञानता-
वश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सालवाला के रिकार्ड में
10-8-1988 दर्ज की गई है जो गलत है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफेत सूचित किया जाता
है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक

28-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असातन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र उपा देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 28-02-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

डा० एम० पी० सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत डा० एम० पी० सूद (हि० प्र० से०), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री पंच राम पुत्र लायक राम, निवासी गांव बठाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पंच राम पुत्र लायक राम, निवासी गांव बठाना, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके बच्चों का जन्म दिनांक 29-12-1994 व 16-10-1996 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश वह जन्म तिथि ग्राम पंचायत बठाना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असातन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र श्री पंच राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 26-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डा० एम० पी० सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

व अदालत डा० एम० पी० सूद (हि० प्र० से०), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

व मुकद्मा :

श्री सोहन सिंह पुत्र थोलू राम, निवासी कागू, तहसील शिलाई।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुहस्ती नाम।

उपरोक्त मुकद्दसा उनवान बाला में श्री सोहन सिंह पुत्र थोलू राम, निवासी कागू ने मय बयान हलफिया बयानात/प्रार्थना-पत्र दिया है कि ग्राम पंचायत कांजे भटनोल के रिकार्ड में उसकी पत्नी व बच्चे नाम लखी राम, चमेली देवी, सबिता गलती से ख्यालू राम भाई के नाम पर दर्ज हो गए हैं जबकि उक्त सदस्य उसके परिवार के हैं। इस गलती को दुरुस्त किया जाए।

अतः ग्राम जनता को बजरिए इशतहार सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 27-3-2001 से पूर्व

अपने एतराज असातन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूत पर श्री सोहन सिंह के प्रार्थना-पत्र पर आपत्ती कार्यवाही कर दी जाएगी।

आज दिनांक 27-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

डा० एम० पी० सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश।

व अदालत डा० एम० पी० सूद (हि० प्र० से०) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम विलास पुत्र दुर्गा राम, निवासी गोरखुवाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राम विलास पुत्र दुर्गा राम, निवासी गोरखुवाला, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका विवाह 28-6-2000 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह अपने विवाह की तिथि ग्राम पंचायत गोरखुवाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 27-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित पांवटा में असातन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र श्री राम विलास पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 27-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डा० एम० पी० सूद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश।

व अदालत डा० एम० पी० सूद (हि० प्र० से०), उप-मण्डल दण्डाधिकारी पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

व मुकद्मा :

श्री रती राम पुत्र बीजा राम, निवासी कीणू, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

वनाम

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रती राम पुत्र बीजा राम, निवासी कीणू, तहसील पांवटा ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की नाम मनोषा का जन्म 15-11-1995 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत जन्मा जुनेली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफ़त सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हज़ा स्थित पांवटा में असातन या वकालतन हाज़िर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र श्री रती राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 26-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

डा० एम० पी० सुद,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
(हि० प्र०)।

व अदालत श्री राकेश शर्मा, (हि० प्र० मे०), उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

व मुकद्दमा :

श्री रूप सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी ग्राम सूर्य नंनाहां,
ग्राम पंचायत पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

साम जनता

श्री रूप सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी ग्राम सूर्य नंनाहां,
तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में
दरखास्त गुजारी है कि उसके पुत्री कु० कौशल्या देवी की जन्म तिथि
26-3-1981 है परन्तु ग्राम पंचायत पंजाहल के रिकार्ड में 26-3-1986
दर्ज है और उसके पुत्र बलवीर सिंह की जन्म तिथि 3-1-1979 है
परन्तु पंचायत रिकार्ड में 3-1-1982 दर्ज की गई है जिसकी वह
दुरुस्ती करवाना चाहता है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
पंजाहल से रिपोर्ट ली गई जिसने उनके जन्म तिथि गलत दर्ज किए
जाने वाले पुष्टि की है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम सूर्य नंनाहां, तहसील नाहन
एवं श्री रूप सिंह पुत्र रतन सिंह के समस्त रिश्तेदारों को सूचित
किया जाता है कि यदि किसी को रूप सिंह पुत्र रतन सिंह की पुत्री
कौशल्या देवी व पुत्र बलवीर सिंह की जन्म तिथि दुरुस्त कराने वाले
कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 28 मार्च, 2001 प्रातः
10.00 बजे अदालत हज़ा स्थित नाहन में असातन या वकालतन
हाज़िर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई
आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र श्री रूप सिंह पर
नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10 मार्च, 2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय
मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

राकेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री राकेश शर्मा, (हि० प्र० मे०), उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश

व मुकद्दमा :

श्री मान चन्द पुत्र श्री लेख राज, निवासी ग्राम सकेती, तहसील नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

ग्राम जनता

श्री मान चन्द पुत्र श्री लेख राज, निवासी ग्राम सकेती, तहसील नाहन
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरखास्त गुजारी
है कि उसके पुत्र का नाम गलती से ग्राम पंचायत काला ग्राम्ब के
रिकार्ड में विनोद कुमार दर्ज करवा दिया गया है। उसका सही नाम हर
चरण है जिसकी दुरुस्ती वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में करवाना
चाहता है।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी,
काला ग्राम्ब से रिपोर्ट ली गई जिसने पुष्टि की है कि श्री मान चन्द
पुत्र श्री लेख राज, निवासी ग्राम सकेती, तहसील नाहन के पुत्र का
नाम ग्राम पंचायत ग्राम्बवाला के रिकार्ड में विनोद कुमार दर्ज है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम सकेती, तहसील नाहन
व श्री मान चन्द पुत्र श्री लेख राज के रिश्तेदारों को सूचित किया
जाता है कि यदि किसी को श्री मान चन्द के पुत्र हर चरण के नाम
की दुरुस्ती ग्राम पंचायत काला-ग्राम्ब के रिकार्ड दर्ज में करवाने
हेतु कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 28 मार्च, 2001 प्रातः
10.00 बजे तक अदालत हज़ा स्थित नाहन में असातन या वकालतन
हाज़िर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई
आपत्ति प्राप्त न होने की सूत में प्रार्थना-पत्र श्री मान चन्द पर
नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10 मार्च, 2001 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय
मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

राकेश शर्मा,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश।

व अदालत श्री देवेन्द्र सिंह कंवर, उप-पंजीपाल, राजगढ़ जिला, सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश

उनका मुकद्दमा :

श्री हरी श्रोम खेड़ा पुत्र दौलत राम निवासी व तहसील राजगढ़,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
* फरीक अब्बल।

विषय:—प्रार्थना-पत्र वावत किये जाने पंजीकृत बसीयतनामा जं०-धारा
40-41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908।

नोटिस बनाम ग्राम जनता को सूचित किया जाता है कि दौलत राम
पुत्र कृष्ण लाल, निवासी व तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल
प्रदेश ने अपने जीते जी पूर्ण-होश-हवास व हक के एक बसीयतनामा
रुबगुह गवाह अपनी जायदाद बोहलटालिया व नेहरपाल को जमीन के
हकदार उसके दो बेटे सर्वेश्वर हरी श्रोम खेड़ा, व शिव कुमार बगवर के
हकदार होंगे तथा राजगढ़ की जिरनी सम्पत्ति या जमीन है उसके
बारिम हरी श्रोम खेड़ा, शिव कुमार व अमर नाथ की पत्नी तथा बच्चों व
उनकी पत्नी बराबर के हकदार होंगे। दौलत राम पुत्र कृष्ण लाल
ने उपरोक्त अपने जायज बारमान के नाम एक बसीयतनामा तहरीर
करवाया था जिसे पंजीकृत किया जाना है।

इसलिए इस इशतहार द्वारा ग्राम जनता को सूचित किया जाता
है कि यदि इस बसीयतनामा को पंजीकृत करने वाले किसी को कोई
उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर असातन या वकालतन
दिनांक 27-3-2001 को अदालत मुकाम राजगढ़ में प्रातः 10.00 बजे
उपस्थित होकर पंज करे अन्यथा वह बसीयतनामा हस्त जाब्ता पाकर
नियमानुसार पंजीकृत किया जाएगा।

आज दिनांक 19-1-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत
में जागे किया गया।

मोहर।

देवेन्द्र सिंह कंवर,
उप-पंजीपाल,
राजगढ़, जिला सिरमौर,।

व अदालत श्री प्रवीण कुमार टाक, कार्यकारी दण्डाधिकारी कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

व अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना०), अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रेखा देवी पुत्री श्री तारू राम, निवासी लारेन्स स्कूल सनावर, तहसील कसौली, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश

श्री शादी खान पुत्र श्री भूरे खान, निवासी डटल, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

वनाम

वनाम

ग्राम जनता

ग्राम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती रेखा देवी पुत्री तारू राम, ग्राम सनावर, तहसील कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में एक दरखास्त प्रस्तुत की है कि उसके पुत्र (बालेश कुमार) का जन्म 26-10-1980 को मेरे मायक लारेन्स स्कूल, सरबेंट क्वार्टर में हुआ था जिसका पंजीकरण ग्राम पंचायत में न करवा सकी। अब करवाना चाहती है।

श्री शादी खान पुत्र श्री भूरे खान पुत्र श्री अल्ला दित्त, निवासी डटल ने इन अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री भूरे खान पुत्र श्री अल्ला दित्त की मृत्यु दिनांक 21-2-1972 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत डटल के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को बालेश कुमार पुत्र सुरेश व श्रीमती रेखा देवी के जन्म पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 28-3-2001 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पंजीकरण हेतु आदेश दे दिये जायेंगे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 28-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री शादी खान पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14-2-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

आज दिनांक 17-2-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रवीण कुमार टाक,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कसौली, जिला सोलन
(हि० प्र०)।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डल अधिकारी (ना०),
अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)।

व अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना०), अम्ब तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

व अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना०), अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती नीलम कुमारी पत्नी श्री बच्चन सिंह, निवासी तलवाल, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री मिरचू राम, निवासी नारी चिन्तपूर्ण, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

वनाम

वनाम

ग्राम जनता

ग्राम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नीलम कुमारी पत्नी श्री बच्चन सिंह निवासी तलवाल ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है उसकी लड़की का नाम शिवानी जन्म दिनांक 2-2-1996 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटोहड़ कला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री मिरचू राम पुत्र लॉगा राम, निवासी नारी चिन्तपूर्ण ने अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री मिरचू राम पुत्र श्री लॉगा राम की मृत्यु दिनांक 16-4-1963 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत नारी चिन्तपूर्ण के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 28-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती नीलम कुमारी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 28-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित अम्ब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री रमेश चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 17-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

आज दिनांक 17-2-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डल अधिकारी (ना०), अम्ब,
तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,
उप-मण्डल अधिकारी (ना०),
अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री नरेन्द्र शर्मा, उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना०) अम्ब, ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश तहसील व जिला ऊना

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री रणकिया राम पुत्र भगत राम, निवासी रुलंग, जिला मण्डा (हि० प्र०)।

मुकद्मा : जन्म तिथि प्रमाण-पत्र

बनाम

सुशील कुमार

बनाम

ग्राम जनता पंजावर

ग्राम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री रणकिया राम पुत्र श्री भगत राम, निवासी रुलंग ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गूजारा है कि उसके पिता श्री रणकिया राम पुत्र भगत राम की मृत्यु दिनांक 28-11-2000 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कारना, तहसील अम्ब, जिला ऊना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

श्री सुशील कुमार पुत्र जम बहादुर, निवासी गांव पंजावर, तहसील व जिला ऊना ने इस न्यायालय में दरखास्त दी है कि उसके पिता अभिषेक कुमार का नाम पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज करवाया जा सका है और अब दर्ज करवाया जावे। इसके पूर्व व जन्म तिथि 5-10-1997 है। तथा बच्चे का जन्म गांव पंजावर है।

अतः संबंधधारण का इन इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को कोई उधर व एनेराज हो तो वह दिनांक 28-3-2001 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हुआ स्थित अम्ब में अनालनन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतहाज दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात आपत्ति प्राप्त न होने की शुरुत में प्रार्थना-पत्र श्री प्रकाश चन्द पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः इन नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्ध रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उसका नाम दर्ज करवाने बार कोई उजर/आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-3-2001 को प्रातः दस बजे स्वयं अथवा असातनन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 17-02-2001 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

आज दिनांक 13-2-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र शर्मा,

मोहर।

हस्ताक्षर/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना०),
अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,
तहसील व जिला ऊना।

भाग 6 भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

-शून्य-

भाग 7 भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं

-शून्य-

अनुपूरक

-शून्य-

भाग—3

कार्मिक विभाग (नि०-11)

उपाबन्ध "क"

अधिसूचना

शिमला-2, 24 फरवरी, 2001

संख्या पर (ए०पी०बी०) बी(2)-9/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सचिवान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

ए०के० गोंस्वामी,
मुख्य सचिव।

हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

- | | |
|--|--|
| 1. पद का नाम | वरिष्ठ सहायक |
| 2. पदों की संख्या | 16 (सोलह) |
| 3. वर्गीकरण | वर्ग-III (अराजपत्रित)
(लिपिक वर्गीय सेवाएं)। |
| 4. वेतनमान | ₹ 5800-200-7000-220-8100-275-9200. |
| 5. चयन पद अथवा अचयन पद | अचयन |
| 6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु। | लागू नहीं। |
| 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएँ। | अनिवार्य : लागू नहीं
वांछनीय अर्हताएं : लागू नहीं |

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ?
9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।
- (i) कनिष्ठ सहायकों में से जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में (31-3-1998) तक की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके उक्त संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य सरकारी विभागों में इस पद पर समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा।
- (ii) उपरोक्त खण्ड (i) में विद्यमान किसी बात के होते हुए भी जो पदधारी प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं वह हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएँ चयन बोर्ड में आमेलित होने के लिए विकल्प देंगे यदि वह खण्ड (i) में निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूर्ण करते हैं तथा जो पदधारी आमेलन का विकल्प देंगे वह इस पद के प्रारम्भिक कैंडिडेट का गठन करेंगे एवं तत्पश्चात् उक्त खण्ड (i) में यथा उपस्थित प्रोन्नति की पद्धति अपनाई जाएगी।
- (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-98 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुस-

आयु : लागू नहीं
शैक्षणिक अर्हताएँ : लागू नहीं

वाँ वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि मध्यम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा।

(i) कनिष्ठ सहायकों में से जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में (31-3-1998) तक की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके उक्त संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य सरकारी विभागों में इस पद पर समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा।

(ii) उपरोक्त खण्ड (i) में विद्यमान किसी बात के होते हुए भी जो पदधारी प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं वह हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएँ चयन बोर्ड में आमेलित होने के लिए विकल्प देंगे यदि वह खण्ड (i) में निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूर्ण करते हैं तथा जो पदधारी आमेलन का विकल्प देंगे वह इस पद के प्रारम्भिक कैंडिडेट का गठन करेंगे एवं तत्पश्चात् उक्त खण्ड (i) में यथा उपस्थित प्रोन्नति की पद्धति अपनाई जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-98 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुस-

रण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निदिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है; वहाँ अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उनसे बराबर सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे।

परन्तु उन सभी पदधिकारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी।

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तु की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उसमें कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र नमूना जाएगा।

स्थापनाकरण—आन्तरिक परन्तु के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि बरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूत-पूर्व सैनिक हैं जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्म्ड फोर्सन एग्जोसल (रिज्रेशन आफ वेकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्निकल सर्विसिज) क्लज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिज्रेशन आफ वेकेंसीज इन दो हिमाचल प्रदेश टैक्निकल सर्विसिज) क्लज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थापनाकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी।

परन्तु 31-3-1998 तक की गई उपर्युक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थापनाकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागोय प्रोन्नति नमिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।

जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।	3. Classification	Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services.
14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा।	लागू नहीं	4. Scale of pay	Rs.5800-200-7000-220-8100-275-9200.
15. सीधे भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।	लागू नहीं	5. Whether selection post or non-selection post.	Non-selection
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी। लागू नहीं	6. Age for direct recruitment.	Not applicable
17. विभागीय परीक्षा	लागू नहीं	7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Essential qualification : Not applicable Desirable qualifications: Not applicable
18. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।	8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Age : Not applicable Educational qualifications: Not applicable
		9. Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
		10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion failing which by deputation/transfer.
		11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer is to be made.	(i) By promotion from amongst the Junior Assistants who possess five years regular service or regular combined with continuous <i>ad hoc</i> (rendered upto 31-3-1998) service, if any, in the grade, failing which by deputation from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale of this post from H.P. Secretariat/H. P. Public Service Commission/Other Government Departments. (ii) Notwithstanding anything contained in clause (i) <i>supra</i> , the incumbents already taken on deputation shall be given option for absorption in the office of H. P. Subordinate Services Selection Board provided that they fulfil the requisite eligibility criteria as laid down in clause (i) <i>supra</i> , the incumbent(s) who opts for absorption shall from the initial cadre of the post and thereafter the method of promotion shall be resorted to as provided in clause (i). १

[Authoritative English text of Government Notification No. Per (AP.B)B(2)-9/99, dated 24-02-2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT (Apptt. II)

NOTIFICATION

*Shimla-171 002, the 24th February, 2001

No. Per (AP.B) B (2)-9/99.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the H. P. Subordinate Services Selection Board as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These Rules shall be called the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Senior Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

By order,

A. K. GOSWAMI,
Chief Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR ASSISTANT (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE OFFICE OF H. P. SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD

1. Name of the post Senior Assistant
2. Number of posts 16 (Sixteen)

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length

of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that :

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998, followed by regular service/appointment), in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment/promotion had shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/

promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of R & P Rules :

Provided that *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.

As required under the law

14. Essential requirement for a direct recruitment.

Not applicable

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.

Not applicable

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination

Not applicable

18. Powers to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 फरवरी, 2001

संख्या मुद्रण (बी) 2-29/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्त्वक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श में, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मोनो सुपर कास्टर वर्ग-III (अराजपत्रित) अल्पिक वर्गीय सेवाओं के पदों के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मोनो सुपर कास्टर वर्ग-III (अराजपत्रित) अल्पिकीय वर्गीय सेवाओं, भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्याख्या.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 14-26/75-शरोमु (स्था0)-II, तारीख 20-9-1979 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग तृतीय

श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा तकनीकी) सेवा (भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य शर्तों) नियम, 1979 का उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, जहाँ तक कि ये वरिष्ठ अक्षर ढालक के पद को लागू हों।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, वात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
विज्ञापक एवं सचिव।

उपाखण्ड "क"

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश में मोनो सुपर कास्टर वर्ग-III के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम मोनो सुपर कास्टर
2. पदों की संख्या 1 (एक)
3. वर्गीकरण वर्ग-III (अग्रजपवित) अलिपि वर्गीय सेवाएँ।
4. वेतनमान श्रेणी 4020-120-4250-140-4400-150-5000-160-58000-200-6200.
5. चयन पद अथवा अचयन पद अचयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु 18 से 40 वर्ष।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए उच्चतम आयु सीमा तदर्थ य. संविदा पर नियुक्त किये गए पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में गिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही गिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के माधुरण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में शामिलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत

पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द की भर्ती की जायेगी जो बाद में ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से शामिल किये गये हैं/किए गये थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें की पद (पदों) को यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्धश्रुति अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।

अनिवार्य अर्हताएँ :
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/बोर्ड से 10वीं पास या हायर सेकेंडरी पार्ट-I या इसके समतुल्य हो।

(ii) किसी मोनो टाईप स्कूल या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से मोनो कास्टर/सुपर कास्टर ट्रेड में नेशनल ट्रेड/शिक्षता प्रमाण-पत्र या इसके समतुल्य।

(iii) चयन मोनो सुपर कास्टिंग मशीन प्रचालन में व्यवहारिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

वाञ्छनीय अर्हताएँ :
हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ, प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।

आयु : लागू नहीं
शैक्षणिक अर्हताएँ : लागू नहीं

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थाना-न्तर्ण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती करने वाले व्यक्तियों की प्रतिभत्ता।

शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11 प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में धेष्णियां जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा।

मोनो कास्टरी में से प्रोन्नति द्वारा जिसका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवा काल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथावहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो निर्धारित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निदिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे करिष्ठ सभी श्रेष्ठ विचार किए जाने के पात्र समझ जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे।

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अहिता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में बिहित सेवा जो भी कम हो, होगी।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण.— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रुलज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स सर्विसमें (रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसिज) रुलज,

1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इस प्रकार म्याचीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति में पद 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी।

परन्तु 31-3-1998 तक की गई उपर्युक्त निदिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

किमी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा प्रवधारित किया जायेगा।

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

लागू नहीं

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

16. आरक्षण

17. विभागीय परीक्षा

18. शिथिल करने की शक्ति

[Authoritative English text of this department notification No. Mudran (B)2-29/99, dated 20-2-2001 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th February, 2001

No. Mudran (B) 2-29/99.—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the H. P. Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Mono-Super Caster Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial Services in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mono Super Caster (Class-III Non-Gazetted) Non-Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2001.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and Savings.*—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Class-III (Ministerial and Technical) Services (Recruitment, Promotion and certain conditions of Services) Rules, 1979 notified vide this department notification No. 14-26/75, Shromu (Satha)-II, dated 20-9-1979 are hereby repealed to the extent these are applicable to the post of Mono Super Caster.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

Sd/-

F. C.-cum-Secretary.

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MONO SUPER CASTER (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY, HIMACHAL PRADESH

- | | |
|--|--|
| 1. Name of the post | Mono Super Caster |
| 2. Number of posts | 1 (One) |
| 3. Classification | Class-III (Non-Gazetted)
Non-Ministerial Services |
| 4. Scale of pay | Rs. 4020-120-4260-140-
4400-150-5000-160-5800-
200-6200. |
| 5. Whether selection post or non-selection post. | Non-selection |
| 6. Age for direct recruitment. | Between 18 years and 40 years: |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government :

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H. P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational qualifications required for direct recruits.

Essential Qualification :

(i) Matric or Higher Secondary Part-I or its equivalent from a recognised University/ Board.

(ii) National Trade/Apprenticeship Certificate in the trade of Mono Caster/Mono Super Caster or its equivalent from a Monotype School or a

Institution duly recognised by the Central/State Government.

- (iii) Selection will be made on the basis of practical test in operating Mono Super Casting Machine.

Desirable Qualification:

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.

Age: Not applicable
Educational Qualifications: Not applicable.

9. Period of probation, if any.

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

100% by promotion failing which by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.

By promotion from amongst the Mono-Caster who possess three years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service, if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998) in the feeder post in view of the provisions referred to above,

all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules :

Provided that the *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998, as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.	16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
14. Essential requirements for a direct recruitment.	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.	17. Departmental Examination.	Not applicable
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc., of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.	18. Powers to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

भाग-5

व अदालत प्रशासक (अतिरिक्त उपायुक्त) सप्लन मण्डी, सोलन जिला सोलन (हि0 प्र0)

नोटिस वनाम :

बोलीदारान/खरीददारान/बारिसान बावत प्लाट वाका सप्लन मण्डी, सोलन, तहसील व जिला सोलन व जनता ग्राम ।

सप्लन मण्डी, सोलन तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में बोलीदारान जिनका विवरण नीचे दिया जाता है, ने सन् 1940 में, जब यह क्षेत्र पटियाला रियासत में था, प्लाट मकानात/दुकानात के निर्माण हेतु नीलामी में सरकार से खरीद किये थे । परन्तु शरामत नीलामी व नियम के अनुसार सप्लन मण्डी बोलीदारान में किसी ने

मकानात/दुकानात का निर्माण नहीं किया है यदि निर्माण किया है तो अन्य व्यक्तियों ने जिसने निर्माण किया है उसके पास प्लाट की खरीद का कोई प्रमाण नहीं मिला है । यह निर्माण एक निश्चित अवधि के अन्दर करना था । आप बोलीदारान/खरीददारान/बारिसान बावजूद इतिलाह हाजिर अदालत नहीं आ रहे हैं ।

अतः आप बोलीदारान/खरीददारान/बारिसान को इस इस्तहार द्वारा सूचित किया जाता है और मौका दिया जाता है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन से 20 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हाजिर आवें । शरायत नीलामी व नियम सप्लन मण्डी की उलघना में प्लाट को वहक सरकार हिमाचल प्रदेश मय रकम जमा शुद्धा जस्त कर लिया जावेगा । बाद मुजर जाने मियाद 30 दिन आपका कोई उजर एतराज नहीं सुना जावेगा ।

प्लाटों का विवरण इस प्रकार से है

नं० सुमार	नाम बोलीदारान	ब्लाक नम्बर	प्लाट नम्बर	रकबा	रकम नीलामी	जमा शुद्धा	बकाया	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री मरघा राम, निवासी भोगलान, जिला पटियाला द्वारा श्री रमेश कुमार पुत्र मरघा राम, F-140, राजपुरा कालोनी, पटियाला	IV	16	40 × 20 = 800 वर्ग फुट	500.00	500.00	—	—
2.	श्री सदानन्द पार्क, लाहौर द्वारा	V	97	20 × 30 = 600 वर्ग फुट	440.00	440.00	—	—
1.	श्री मनी बीना अरोड़ा विधवा सुभाष अरोड़ा C/O सुभाष मिलज, 77/1, कानपुर।	V	98	20 × 30 = 600 वर्ग फुट	475.00	475.00	—	—
2.	डा० उषा शोम प्रकाश, बम्बई							
3.	डा० विमला मांगा, नई दिल्ली							
4.	डा० निर्मला गुप्ता, कानपुर							
5.	डा० प्रोमिला गुप्ता, मध्य प्रदेश							
				कुल (3 प्रकरण)				

आज दिनांक 12-3-2001 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

सुभाष कलशोला,
(प्रशासक अति० उपायुक्त),
सप्लन मण्डी, सोलन (हि० प्र०) ।